खण्ड–4,जूलाई–अगस्त–2020

Centre for Advocacy and Research

कोविड-19 रिस्पोंस न्यूजलेटर

कार्यकारी निदेशक की डेस्क से

कोविड–19 महामारी के लगभग आधे साल बाद भारत में सामान्य जीवन पटरी से उतर गया है। इसने समाज के सामने आईना रख कर उसकी वास्तविक तस्वीर भी दिखा दी है। यह एक सुखद तस्वीर नहीं है क्योंकि यह हमारे गरीबों की अरक्षितता दर्शाती है। इसने सबसे अच्छे समय में भी उनकी सबसे बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में उनकी कठिनाइयों और उनको ध्यान में रख कर बनाई गई सार्वजनिक प्रणालियों के तहत उन्हें मिलने वाले न्यूनतम एवं अलग से समर्थन देने में नाकामी भी उजागर की। यहां एक प्रासंगिक सवाल यह है कि क्या लोगों को जान–बूझकर इस समर्थन से बाहर रखा जा रहा है, जबकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी योजनाएं उनके लिए ही बनाई गई थीं। हम अभी भी भारतीय शहरों के सबसे कमजोर लोगों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए उनका समर्थन करते हैं और उनकी हकदारियों के बारे में सरकार एवं अन्य संबंधित विभागों के साथ पैरवी भी कर रहे हैं। यह उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि कोविड–19 महामारी ने भारत में एक गहरा प्रवासी संकट पैदा किया है। हमारे न्यूजलेटर ने उन आम लोगों की आवाज उठाई है, जो कार्यक्रमों के हाशिए पर थे और वहीं बने हुए हैं। यदि नई और पुरानी योजनाओं से व्यापक लाभ होने लगे तो उन्हें पहले पता लगना चाहिए। यह न्यूजलेटर उनके सरोकारों – उनके घरों में अभी भी भोजन की कमी, आजीविका के बहुत कम अवसर, उनके बच्चों की शिक्षा की समस्या और अन्य चुनौतियों को प्रस्तुत करता है। साथ ही, इसमें कोविड–19 महामारी के डर, बदलती परिस्थितियों और प्रभावों को प्रस्तुत किया गया है। हम बहुत शीघ्र ही देश के एक भिन्न हिस्से से उनकी आवाज आपके सामने लाएंगे।

अखिला सिवदास

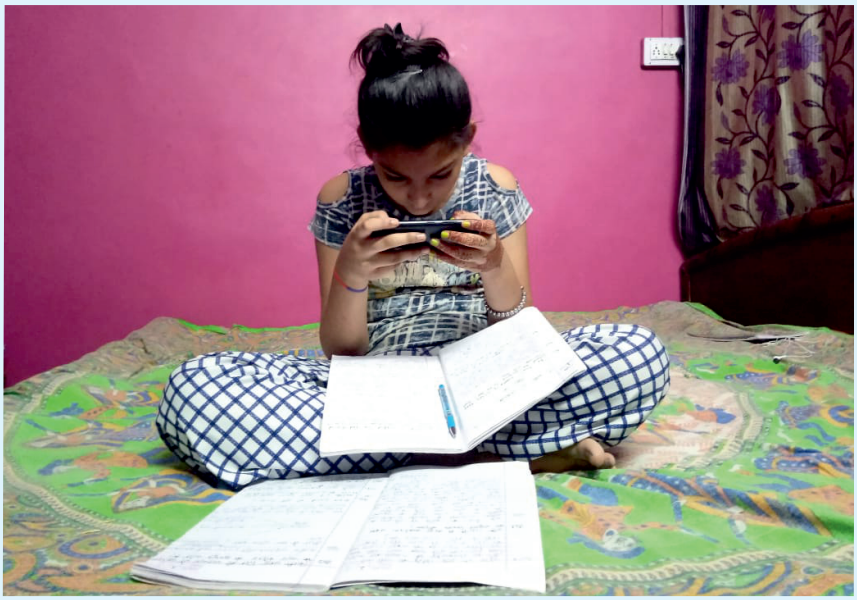

गरीब माता–पिता कहते हैं –ऑनलाइन शिक्षा उनके बच्चों के लिए व्यावहारिक कदम नहीं

नई दिल्ली, जयपुर, अजमेर, जोधपुर : कोविड–19 महामारी से बच्चों की शिक्षा एक बहुत बड़ी मुसीबत बन कर सामने आई है और गरीब समुदाय सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। सीफार (सी.एफ.ए.आर.) देश के जिन शहरों में समाज के गरीब और हाशिए पर जी रहे वर्गों के साथ कार्य करता है, वहां के परिवारों ने बताया कि शिक्षा का कार्य ''बिल्कुल नहीं चल रहा है'' और इस मामले में बिना किसी प्रगति के बच्चे तथा माता–पिता दोनों ''संघर्ष'' करने को विवश हैं।

पूर्वी दिल्ली के खिचड़ीपुर की प्रिया बताती हैं– ''लगभग 7 प्रतिशत बच्चे सरकारी स्कूलों के छात्र थे, जबकि बाकी निजी स्कूलों में जाते थे। स्कूलों द्वारा पूरी फीस वसूलने और महत्वपूर्ण बात– टेक्नोलॉजी (प्रौद्योगिकी) आधारित शिक्षा की ओर मुड़ने से लोगों की कठिनाइयां बेतहाशा बढ़ गई हैं।''

वह आगे कहती हैं– ''निजी स्कूल पूरी फीस वसूल रहे हैं। जबकि लोगों के पास नौकरी नहीं है या चुकाने को पर्याप्त धनराशि नहीं है।'' उनके पास स्मार्टफोन या टैबलेट और कंप्यूटर जैसे गैजेट नहीं हैं। वह कहती हैं– ''वे अपने बच्चों को तकनीकी रूप से समर्थन देने में सक्षम नहीं हैं।'' जोधपुर स्थित माता के कुंड की कौशल्या ने इस समस्या को इन शब्दों में बयां किया– ''कोई शिक्षा नहीं चल रही है। गैजेट–आधारित शिक्षा पाने की दृष्टि से समुदाय के परिवार बहुत गरीब और असक्षम हैं।'' दिल्ली और जयपुर सहित अनेक शहरों के सामुदायिक सदस्यों ने बताया कि कई बच्चों के माता–पिता अनपढ़ हैं, जिससे टेक्नोलॉजी के बारे में उनकी समझ बहुत कम है। दिल्ली, जयपुर, जोधपुर और अजमेर में स्कूल जाने वाले बच्चों के माता–पिता ने इसी तरह की प्रतिक्रिया प्रकट की।

उन्होंने गैजेट खरीदने में असमर्थता, इंटरनेट कनेक्शन का अभाव और माता–पिता की तकनीकी अक्षमता को मुख्य कारण बतलाया, जिनसे ऑनलाइन शिक्षा पाने का काम प्रभावी रूप से नहीं हो रहा है। अनेक परिवारों के पास केवल एक स्मार्टफोन है, जिसको ज्यादातर मामलों में बच्चों के पिता रखते हैं क्योंकि उन्हें पूरे दिन घर से दूर रहना पड़ता है। अजमेर की चंदा ने कहा– ''कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाती हैं। यदि इनके वास्तविक समय यानी सुबह में स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं हो तो बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता है या शाम को पिता के वापस आने पर उनसे स्मार्टफोन एकदम ले भी नहीं सकता।''

दिल्ली के स्कूल अपने विद्यार्थियों के माता–पिता को टेक्नोलॉजी के बारे में सीखने में मदद की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन, यह अनेक परिवारों के लिए उपयोगी नहीं है क्योंकि माता–पिता को नए कौशल सीखने में कठिनाइयां होती हैं। प्रिया ने बताया– ''हमें गैजेट्स के उपयोग का केवल बुनियादी कौशल ही प्राप्त हैं।'' दूसरी कठिनाई यह है कि जब बच्चों के पास गैजेट होता है तो वे पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर की विजय कंवर का कहना है कि अगर बच्चों के पास स्मार्टफोन होता है तो वे आसानी से विचलित हो जाते हैं और शिक्षक पर ध्यान देने के बजाए गेम खेलना या एप्लिकेशन के उपयोग को तवज्जो देते हैं। उन्होंने बताया– ''ऑनलाइन कक्षाओं के साथ–साथ ऑनसाइट कक्षाएं व्यावहारिक रूप से उपयोगी साबित नहीं हो रही हैं। इन कक्षाओं के दौरान हर समय बच्चों की निगरानी करना असंभव है।''

एक अन्य समस्या असाइनमेंट शीट्स का प्रिंटआउट पाने से संबंधित है। विजय कंवर आगे बताती हैं– ''स्कूल कागज पर होमवर्क और असाइनमेंट करना आवश्यक बताते हैं, जबकि वे स्वयं दस्तावेजों के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण भेजते हैं, जिनका माता–पिता द्वारा प्रिंट लेना आवश्यक है। अनेक मामलों में विद्यार्थियों द्वारा इन शीट्स को पूरा करने के बाद स्कूल में पहुंचाया जाता है। लेकिन, झुग्गी–झोपड़ियों और पिछड़े इलाकों में रहने वाले गरीब परिवारों के बच्चों के पास प्रिन्टिंग (मुद्रण) और इंटरनेट की सुविधाओं तक आसान पहुंच नहीं होती। प्रिन्टिंग का खर्च भी उन्हें हतोत्साहित करता है।''

''छोटे कारोबार हो गए हैं बर्बाद, नौकरियां की कमी से जूझ रहे हैं लोग''

नई दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, अजमेर : शहरों में ट्रैफिक की भीड़ या रौनक वापस लौट सकती है, लेकिन नौकरी नहीं। उन घरेलू नौकर–नौकरानियों, ड्राइवरों, कैजुअल वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और उन सभी के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं, जिन्होंने कोविड–19 महामारी के दौरान अपनी नौकरियां गंवाई हैं या जिनके रोजगार की शर्तें अनिश्चित हैं। यहां तक कि वर्तमान में जो कुछ नौकरियां उपलब्ध हैं, उनकी शर्तें बदल गई हैं। सीफार (सी.एफ.ए.आर.) जमीनी स्तर पर स्थिति की निगरानी कर रहा है और उन परिवारों की सहायता कर रहा है, जो अभी भी महामारी के काले साये से उबर नहीं पाए हैं। सीफार उत्तर भारत के कई शहरों में कार्यरत है, जिनके अनेक लोगों ने बताया कि वे बहुत कम आय या उधार लिए गए धन से गुजारा चला रहे हैं।

जयपुर के अमागढ़ कॉलोनी, ट्रांसपोर्ट नगर में सीफार की सामुदायिक प्रबंधन समिति के सदस्यों में से एक विजय ने बतलाया कि कुछ कारोबार आंशिक रूप से फिर शुरू हो गए हैं, लेकिन नाई या हलवाई (मिठाई बनाने वाला) जैसी नौकरियों की कोई मांग नहीं है। उन्होंने आगे कहा– ''हमारे इलाके और अन्य सभी इलाकों में नाई और हलवाई बिना कार्य के अपने घरों में बैठे हैं। उनकी अब आवश्यकता नहीं रही है क्योंकि शहर का जीवन अवरूद्ध हो गया है। पहले हलवाई हमेशा पूरियां और मिठाई बनाने एवं परोसने में जुटे रहते थे, जबकि नाई की दुकानों पर हमेशा ग्राहक दिखाई देते थे। लेकिन, अब कोविड–19 महामारी के डर से सभी को बाहर खाने या नाई के पास जाने से डर लगता है।''

दिल्ली स्थित कल्याणपुरी की जशोदा का कहना है कि कार्य की उपलब्धता में भारी गिरावट आई है और पुरुषों के साथ–साथ महिलाएं भी घर पर रहने को विवश हैं। उनके इलाके की महिला निवासी अधिकांशतया घरेलू नौकरानियों के रूप में कार्य करती थीं, जिनकी अब मांग नहीं है। वह आगे बताती हैं– ''लोग इन्हें काम करने के लिए नहीं बुला रहे हैं। कुछ लोग उन्हें एक सप्ताह में केवल दो या तीन बार बुला रहे हैं। इससे लोगों के घरों में काम जमा होता जाता है, जिससे उन्हें बढ़े हुए कार्य करने पड़ते हैं, लेकिन उनके एवज में उन्हें पूरा भुगतान नहीं किया जा रहा है।''

यहां तक कि श्रमिकों को कम भुगतान करने के लिए पिछली कार्य व्यवस्था को बदल दिया गया है। उदाहरणार्थ, कोविड–19 महामारी से पहले प्रिया को 7.5 किलो (किलोग्राम) खिलौनों की असेम्बिलंग और पैकेजिंग के लिए 80 रु. मिलते थे। इसकी अब मजदूरी 60 रु. तक सिमट गई है। यहां सवाल उठता है कि वह अब कितने किलो तक के खिलौनों की असेम्बलिंग और पैकेजिंग कर पाती हैं? इसके जवाब में वह कहती हैं– ''उसका परिवार मिल कर पूरे दिन काम में जुटता है और 7.5 किलो तक के ही खिलौनों की एक ढेरी की असेम्बलिंग और पैकेजिंग कर पाता है।''

जयपुर के एक कार मैकेनिक राकेश ने बताया कि 90 प्रतिशत छोटे व्यवसाय नष्ट हो गए हैं। उन्होंने कहा– ''छोटे व्यवसायों से मेरा मतलब बहुत छोटे काम–धंधों से है, जैसे– ठेले पर सब्जियां बेचना, पड़ोस में किराने की छोटी–सी दुकान या छिटपुट सामान बेचने वाली दुकान, जिससे लोगों को थोड़ी कमाई हो जाती थी। ऐसे लोगों के अपने संसाधन समाप्त हो चुके हैं और छोटे काम–धंधों के लिए पैसा नहीं बचा है।'' हालांकि राकेश एक कुशल पेशेवर मेकेनिक है, फिर भी उसके कार्य की मांग नहीं हैं। वह जोर देकर कहते हैं– ''लगभग कोई काम नहीं है।''

सीफार की एक कार्यकर्ता ने बताया कि उसके पति के पास एक टैक्सी थी, जिसका लॉकडाउन के बाद पिछले कुछ महीनों में केवल दो बार इस्तेमाल किया गया है। वह कहती हैं– ''मेरे पति निर्माण कार्य (कन्स्ट्रक्शन वर्क) के सबंध में मजदूरों को लाने के लिए अपनी कार से बिहार गए थे। वहां एक ठेकेदार ने उन्हें नौकरी पर रख लिया। लेकिन, सवाल उठता है कि क्या राजस्थान में मजदूर उपलब्ध नहीं हैं?'' दरअसल, ठेकेदार के लिए बिहार से मजदूरों को प्राप्त करना सस्ता पड़ता है।'' लेकिन, बिहार की दो यात्राओं के बाद उसके पति घर पर ही रह रहे हैं। उसने आगे बताया– ''हम अपनी अल्प–बचत पर जी रहे हैं और उधार भी लेना पड़ा है।''

यहां तक कि आय के अभाव या कमी के कारण बारम्बार होने वाले घरेलू खर्चे बेरोकटोक जारी हैं। भोजन और किराने का सामान, बच्चों की शिक्षा एवं किराए के नियमित खर्चे परिवारों का हिस्सा हैं, जिनसे बच नहीं सकते। अधिकांश शहरों में मकान–मालिकों ने आम तौर पर किराए माफ नहीं किए हैं। प्रिया बताती हैं– ''इन मकान–मालिकों में से कुछ समुदाय के लोग ही हैं। वे किराया–राशि चुकाने के लिए किराएदारों को अधिक समय देने पर सहमत हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने किराया माफ नहीं किया है।"

यहां तक कि गरीबों में सर्वाधिक गरीब सबसे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। जोधपुर का फल–विक्रेता हरीश रद्दी माल (स्क्रैप) भी बेचता है और उसके पास एक तीन पहिया वाहन है। उसने बताया कि उसका काम आवश्यक सेवाओं का हिस्सा है और वह इस महामारी के दौरान ''कुछ कमाने'' में कामयाब रहा। लेकिन, वह कहता है– ''मैं ऐसे बहुत–सारे लोगों को जानता हूं, जिन्होंने पिछले कुछ महीनों से कुछ भी नहीं कमाया है। अब भी उनके सामने कार्य के अवसर सीमित हैं और उन्हें यदा–कदा ही कार्य मिलता हैं। यह बहुत कठिन समय है।''

हकदारियां

नए राशन कार्डों का इंतजार, ई–कूपन की बहुत कम तादाद

नई दिल्ली, अजमेर, जोधपुर : कोविड–19 महामारी और लॉकडाउन का एक तत्काल परिणाम अकुशल और स्व–रोजगार में सक्रिय व्यक्तियों की बड़ी संख्या में नौकरियों और व्यवसाय की हानि के रूप में सामने आया है। इससे वे सरकार और समुदाय–आधारित संगठनों द्वारा प्रदान किए गए राशन पर निर्भर होने को विवश हो गए हैं। लॉकडाउन को हटाने के साथ सरकारी समर्थन वापस ले लिया गया, जबकि लोग अपनी आय की हानि से अभी भी उबरे नहीं हैं। अजमेर के गंज इलाके की चंदा ने कहा– ''उन्हें अभी भी बहुत सारी सहायता की जरूरत है ताकि उनके पास खाने को पर्याप्त भोजन हो।''

उसने कहा कि उसके क्षेत्र के अधिकांश लोगों के पास राशन कार्ड हैं, लेकिन उनमें से केवल आधे लोगों के पास ही श्सक्रियश राशन कार्ड हैं। वह बताती हैं– ''ये राशन कार्ड 2013 में बनाए गए, लेकिन जब इनमें से आधे सक्रिय किए गए तो दूसरे आधे असक्रिय रह गए।'' जून, 2020 में सरकार ने केवल एक बार राशन वितरित किया।

दिल्ली के खिचड़ीपुर इलाके के सामुदायिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें दो बार ई–कूपन के माध्यम से सरकार से राशन मिला है। प्रिया ने बताया– ''पहली बार हम ई–कूपन का इस्तेमाल कर सकते थे क्योंकि इन्हें दुकानदारों ने स्वीकार किया, लेकिन दूसरी बार नहीं।'' उसने कहा कि इसका कारण यह है कि पहले ई–कूपन, जो फोन पर आए थे और निर्दिष्ट दुकानों पर भुनाए जाते थे। यह ठीक था, लेकिन दूसरे लॉट (खेप) के ई–कूपन को भुनाया नहीं जा सका। उसके अनुसार "दूसरे लॉट के ई–कूपन पर किसी निर्दिष्ट दुकान का नाम नहीं था, जहां उन्हें भुनाया जाना था। इसलिए, लोग एक दुकान से दूसरी दुकान पर गए और दुकानदारों ने बताया कि ये उनकी दुकान पर भुनाए नहीं जा सकते।''

दूसरा मुद्दा, तमाम कोशिशों के बावजूद परिवारों को राशन कार्ड नहीं मिलना है। जोधपुर की एक सामुदायिक कार्यकर्ता कौशल्या ने कहा कि उनके क्षेत्र में कई परिवार ऐसे थे, जो बिना राशन कार्ड के थे। उन्होंने बताया– ''एक बार बहुत–सारी बातें की गईं कि सभी को राशन कार्ड मिलेंगे और हमने संबंधित सरकारी अधिकारी से बातचीत भी की। इसके बाद कुछ महीने बीत चुके हैं और उनके पास अभी भी राशन कार्ड नहीं हैं।''

प्रवासी संकट के बाद, स्थानीय सरकारी अधिकारियों से उम्मीद की गई थी कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी हकदारी वाले कार्यक्रमों में गरीब लोगों का पंजीकरण करेंगे, जिसके तहत राशन कार्ड प्रदान किए जाते हैं। लगता है कि अब यह तात्कालिकता समाप्त हो गई है।

पूर्वी दिल्ली के खिचड़ीपुर की निवासी जशोदा के मामले पर जरा गौर करें। उसने 2015 में राशन कार्ड के लिए आवेदन किया था। पिछले पांच साल में और उसके बाद अनेक आवेदन देने के बावजूद उसको राशन कार्ड नहीं मिला है। जशोदा दुःखी मन से अपना दर्द बयां करती हैं– ''मैं एक गरीब महिला हूं, जिसने कम वेतन वाले कार्य किए हैं, लेकिन वे अब उपलब्ध भी नहीं हैं। मेरे पास अपनी दैनिक जरूरतें पूरी करने के लिए पैसे नहीं हैं।''

विभिन्न शहरों के अनेक लोगों ने इन पंक्तियों के लेखक को बताया कि भोजन की उपलब्धता अनेक परिवारों के लिए एक मुद्दा है, जबकि सरकार से उन्हें मिलने वाला मामूली समर्थन भी बंद हो गया। प्रिया कहती हैं– ''ऐसे लोग हर जगह हैं।'' बस, व्यक्ति को चारों ओर नजर घुमानी है।

वॉश

जयपुर की बस्तियों में वर्षा के पानी ने घरों में घुस कर फैलाई दुर्गंध और बीमारियां

जयपुर : ''हम वर्षा से डरते हैं''– यह कहना है जयपुर की झुग्गी–बस्ती बाबा रामदेव नगर की निवासी मंजू का। यह भारत में पानी की कमी वाले रेगिस्तानी राजस्थान राज्य की निवासी का एक विचित्र कथन प्रतीत हो सकता है, लेकिन मंजू का सच में यही मतलब है। हर बार जब वर्षा होती है तो नालियां भर कर उनका पानी जोरदार उफान मारते हुए बाहर सैलाब की माफिक बहता है, खराब तरीके से बनाए गए घर टूट–गिर जाते हैं, नलों से गंदे पानी की सप्लाई होती है, जिससे लोग बीमार पड़ जाते हैं और उनका जीवन तकलीफदेह बन जाता है। मंजू अपनी बात जारी रखती हैं– ''जब गंदा पानी लोगों के घरों में घुसता है तो वे चीख–पुकार मचाते हैं। इस पानी में गलियों से निकलने वाला मल–जल और गंदगी होती है। यदि बहुत बारिश होती है तो यकायक लहरों की तरह पानी घर में घुसता है और हमारे सारे सामान, जैसे– कपड़े और गद्दे भीग जाते हैं। जब ऐसा होता है तो लोग हिम्मत हार जाते हैं और निराशा में रोने लगते हैं।''

सीफार (सी.एफ.ए.आर.) ने हाल ही में जयपुर की झुग्गी–बस्तियों में पानी, स्वच्छता और साफ–सफाई की स्थिति पर एक सर्वेक्षण किया। इसके निष्कर्ष इस साल के अंत में जारी किए जाएंगे। विभिन्न क्षेत्रों की अपनी समस्याएं हैं, लेकिन अनेक ऐसे आम मुद्दे हैं, जिनको निवासियों द्वारा निपटाना जाना चाहिए। भीड़भाड़ वाले घरों के साथ झुग्गी–झोपड़ी होने के कारण ये क्षेत्र काफी हद तक अनियोजित हैं। झुग्गी–बस्ती के एक अन्य निवासी विजय कहते हैं– ''बहुत–सारे कच्चे घर हैं। यहां तक कि ईंट के घरों को भी खराब तरीके से बनाया गया है।''

एक वीडियो सीफार के साथ साझा किया गया, जिसमें लगातार वर्षा से ध्वस्त हुए एक घर को दिखाया गया। इस घर के मालिक संजय कहते हैं– ''मेरा घर बह गया है। मेरा सारा सामान चला गया है। हमारे पास खाने के लिए एक निवाला भी नहीं है। हमारे सिर पर छत नहीं है। हम क्या करें? हमें तत्काल मदद की जरूरत है।''

स्थानीय निवासियों द्वारा साझा किए गए अन्य दृश्य में सड़कों पर कमर तक ऊंचे बह रहा पानी, घरों के अंदर घुसे पानी और पानी में डूबे हुए घरेलू सामान दिखाए गए। मंजू कहती हैं– ''यह आम बात है। बारिश होने पर लोगों पर दुःखों की बौछार टूट पड़ती है।''

बारिश से क्षेत्रों में पानी की गुणवत्ता भी खराब होती है। निवासियों ने बताया कि गर्मियों में पानी की किल्लत थी, लेकिन मानसून में पानी की गुणवत्ता में भारी गिरावट आई। मंजू ने कहा कि यहां तक कि नल के पानी के उपयोग से मनुष्य के चेहरे से अक्सर बदबू आती है। वह बताती हैं– ''कल ही, लोगों ने जल–जमाव होने और उस जल से दुर्गंध फैलने की बात कही। उसकी सहेली संजना वर्तमान में जल–जनित बीमारी के कारण दस्त और उल्टी से पीड़ित है।'' उसने आगे कहा– ''ऐसे कई लोग बीमार हैं– उन्हें दस्त, बुखार, सर्दी एवं खांसी, त्वचा की फटन और आंखों में संक्रमण है। निवासी अपने लक्षणों, जैसे– बुखार के बारे में बताने से डरते हैं क्योंकि कहीं उन्हें कॉवेड–19 के संपर्क में आने का संदिग्ध न मान लिया जाए।'' ट्रांसपोर्ट नगर के पास स्थित एक झुग्गी बस्ती के निवासी राजेश ने कहा– ''लोग स्थानीय औषधालयों में जाते हैं, लेकिन कभी–कभी अपनी बीमारियों को छिपाते भी हैं।''

राजेश ने आगे बताया– ''जयपुर में बारिश हो रही है और हर बौछार के साथ, हम पहाड़ी के नीचे बहुत–सारा पानी तेजी से बहते हुए देखते हैं। यह पानी इलाके के बीचों–बीच एक खाई में इकट्ठा होता है।'' एक अन्य निवासी ने कहा कि जल–जमाव ने क्षेत्र के निवासियों के लिए आना–जाना बहुत मुश्किल बना दिया। कचरा संग्रह कथित तौर पर सामान्य समय में कुशलता से नहीं होता है और मानसून के महीनों में तो हालत बदतर हो जाती है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के एक इंजीनियर ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा कि विभाग शहर के जल–जमाव से ग्रस्त क्षेत्रों में पानी के पंपों का उपयोग कर रहा है। उन्होंने बताया– ''मेरे क्षेत्र विद्याधर नगर में पानी की सप्लाई प्रभावित नहीं हुई है।'' एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि झुग्गियां अनियोजित एवं अनधिकृत हैं, इस कारण बहुत खराब तरीके से मकान बनाए गए हैं और इनमें समुचित नागरिक सुविधाओं का अभाव रहता है।

जयपुर नगर निगम के एक अधिकारी ने कहा कि निचले इलाकों में जल–जमाव की संभावना थी। बाबा रामदेव नगर में कुछ ऐसे क्षेत्र थे। उन्होंने बताया– ''एक बाढ़ नियंत्रण कक्ष है, जो बाढ़ से संबंधित शिकायतों का जवाब देने के लिए स्थापित किया गया है।'' सीफार समुदायों के साथ मिल कर काम कर रहा है ताकि सुनिश्चित हो कि वे उन सरकारी एजेंसियों तक पहुंच सकें, जिनकी अपने क्षेत्रों में कार्य करने की जिम्मेदारी है।

आवागमन में समस्या से बाहर कार्य नहीं कर पा रही हैं महिलाएं

नई दिल्ली : दक्षिण दिल्ली के बदरपुर इलाके की निवासी सीमा जब प्रतिदिन अपने घर से बाहर कार्य की जगह पर जाती हैं तो अकेले यात्रा करती हैं। वह अपने घर से बस स्टॉप पर जाती हैं और बस का इंतजार करती हैं। यह एक लंबा इंतजार हो सकता है, लेकिन वह इसके लिए तत्पर है। वह कहती हैं– ''व्यस्ततम समय (पीक ऑवर्स) के दौरान मैं एक बहुत लंबे, संभवतः एक घंटे से भी अधिक समय तक इंतजार कर सकती हूं।''

जब इंतजार और भी लंबा हो जाता है तो वह एक ऑटो–रिक्शा किराए पर लेने की कोशिश करती है, जिसका एकतरफा खर्च लगभग 125 रु. आता है, जिसमें ओवरचार्जिंग भी शामिल है। उसने कहा– ''इसका मतलब है कि मुझे आवागमन के दोनों तरफ के लिए 250 रु. का भुगतान करना पड़ेगा। इस खर्च को वहन करने के लिए मुझे प्रतिदिन इससे अधिक कमाना होगा।''

जब लॉकडाउन हटा दिया गया और कार्य की इजाजत दी गई तो पुरुषों और महिलाओं ने कार्य के लिए बाहर जाना शुरू किया। हालांकि नौकरियों में कमी के चलते महिलाओं (और पुरुषों) के लिए रोजगार तलाशना एक चुनौती है। इनमें से कइयों को काम मांगने के लिए अनेक जगह जाना पड़ता है। दिल्ली परिवहन निगम द्वारा चलाई जा रही सार्वजनिक बसों में वर्तमान सामाजिक दूरी के मानदंडों के अनुसार एक बस में अधिकतम 20 व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं और महिलाओं के लिए सीटों का कोई आरक्षण नहीं है। प्रारंभ में, महिलाएं बस स्टॉप पर पहुंचती हैं और बस में सीट नहीं मिलने पर घंटों खड़े–खड़े यात्रा करती हैं। सीमा बताती हैं– ''या तो बसें भरी हुई होती हैं या पुरुष सुनिश्चित करते हैं कि वे किसी न किसी तरह बस में चढ़ जाएं। जबकि महिलाएं बस में चढ़ने का संघर्ष और कोशिश करती हैं, लेकिन अक्सर पीछे रह जाती हैं।''

दक्षिणी दिल्ली की निवासी भावना का कहना है कि वह कभी भी बस में सीट नहीं पा सकीं, इसलिए अब साझा ऑटो–रिक्शा लेती है। उसने बताया– "मुझे मासिक 12,000 रु. का वेतन मिलता हैं और साझा ऑटो–रिक्शा से आने–जाने पर प्रतिमाह लगभग 3,000 रु. खर्च होते हैं। कभी–कभी, जब मुझे परिवहन का साधन नहीं मिलता है तो मैं काम पर नहीं जाती।"

कई महिलाएं अभी भी बाहर कार्य करने नहीं जा पा रही हैं क्योंकि वे बस में नहीं चढ़ सकतीं या ऑटो–रिक्शा का किराया वहन नहीं कर सकतीं, जो उसके वेतन से कहीं अधिक है। दिल्ली में गौतमपुरी की निवासी सरोज डिफेंस कॉलोनी में घरेलू काम करती थीं। उसने बताया– ''मैंने बस लेने की कई बार कोशिश की, लेकिन बसें हमेशा भरी रहती हैं। मैं हर महीने 7,000 रु. कमाती रही थीं, इसलिए ऑटो–रिक्शा का किराया वहन नहीं कर सकतीं। इसलिए, मैं अभी घर पर ही हूं।

सीमा ने कहा कि पहले बस स्टॉप पर ज्यादा महिलाएं होती थीं और काम पर जाने के लिए बस का इंतजार करती थीं, लेकिन यह संख्या अब कम हो गई है। वह कहती हैं– ''वह अब घर पर ही हैं।''

इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए, दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी (सिटी बसों के प्रभारी नहीं) ने कहा कि कोविड–19 महामारी से निपटने के लिए सामाजिक दूरी एक आवश्यक उपाय है। अगर सरकार को सुझाव दिए जाते हैं तो वह महिलाओं के लिए बस में सीटों के आरक्षण पर विचार कर सकती है।

. – . – . . – .

राहत कार्य के आंकड़े– जुलाई–अगस्त 2020

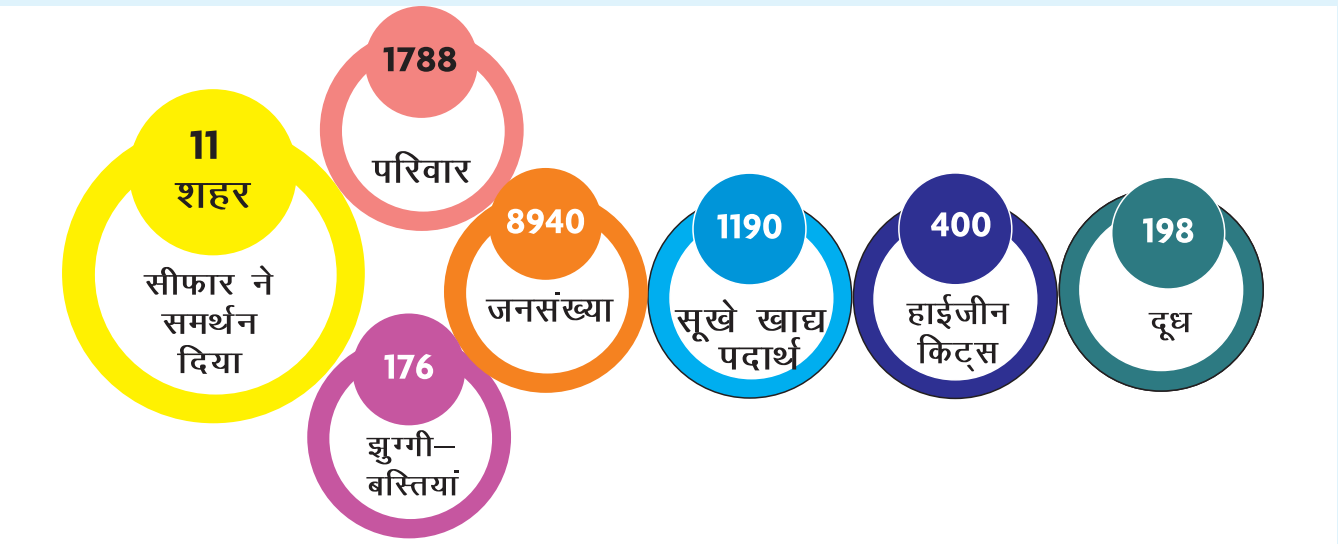

शहर–8	1–30 जून	1–15 जुलाई	16 जुलाई–अगस्त 20	कुल
सूखे खाद्य पदार्थ	11,457	1,715	12,581	25,753
पकाया गया भोजन	8,360		11,824	20,184
अन्त्योदय राशन	30,242	18,522	1,462	50,226
किराना किट	3,582	1,337	9,323	14,242
ए.आर.टी. / औषधियां	232	27	62	321
पोषण अनुपूरक	3,080	3,044	33,900	40,024
वित्तीय सहायता	250	102	50	402
हाईजीन किट	4,262		4,670	8,932
राशन कार्ड			75	75
झुग्गी–बस्ती	242	171	219	632
परिवार	61,465	24,747	74,667	1,60,879
जनसंख्या	3,07,325	1,23,735	3,73,335	8,04,395